श्री दिनेश सिंह : इस बारे में मुझे अपने दोस्त, सूचना और प्रसारण मंत्री, से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस के नियम उन के मंत्रालय में बनते हैं ।

SHRI D. N. PATODIA : This newsprint is being imported through various agencies apart from the STC. In most of the cases including the STC it has been observed that the price at which it is selling in India is very much higher compared to the cost of import. I want to know whether there is a device or a system by which Government is able to get a parity as to whether there is any profit element either by the STC or by anybody else; whether they would get it examined and some sort of system is devised by which all over the country there is some sort of reasonable parity of the price, whether it is imported by the STC or by somebody else.

SHRI DINESH SINGH : This is an attempt that has been made at buffer-stock in this respect; that there is stability of price and there is regularity of supply. Whether there is any disparity between the imported price and the sale price, is a matter that I shall have to examine before I can say something.

नागालैन्ड में कागज बनाने का कारखाना

*1381. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागालैण्ड में एक कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये नागालैण्ड सरकार ने जो सहायता और अनुमति मांगी है, उसके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI) : The Government of Nagaland have appointed a Committe with which some representatives of Central Government are also associated, to look into the economics of a Paper Project in that State. The Report of the Committee is awaited.

श्री महाराज सिंह भारती : मैं अभी पीछे नागालैण्ड गया था । वहां पर बहुत से क्षेत्रों में खालिस बांस के जंगल मैं ने देखे हैं । वहां पर पहाड़ भी कच्चा है, जिस पर बांस आराम से खड़ा हो सकता है । नागालैण्ड सरकार के जिम्मेदारी मंत्रियों ने मुझे बताया कि उन्होंने इस सम्बन्ध में एक प्लान केन्द्रीय सरकार को सबमिट कर दिया है और उन को शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार उन की डेवेलपमेंट की योजनाओं पर जैसे, वे चीनी और कागज की मिलें लगाना चाहते हैं तवज्जह कम देती है और उन के लड़ाई-झगड़ों पर ज्यादा तवज्जह देती है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा बांस नागालैण्ड में मौजूद है और वहां की सरकार ने इस बारे में अपनी सिफ़ारिश कर दी है, तो फिर कागजों के हेर-फेर में उस स्कीम को लागू करने में देर क्यों की जा रही है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : वहां की सरकार ने एडवाइजर्ज के जरिये से एक प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई है । इस वक्त हमारी सैण्ट्रल कमेटी और नागालैण्ड की कमेटी मिल कर उस पर गौर कर रही हैं, ताकि यह देखा जाये कि यह प्राजेक्ट कहां तक वायेबल हो सकती है । इस में देर करने का सवाल नहीं है । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि, जैसा कि आप को मालूम है, नागालैण्ड में जो पेपर बनेगा, वह वहां खर्च नहीं होगा, बल्कि उस को बेचने के लिये कलकत्ता वगैरह दूसरी जगहों में लाना पड़ेगा, जिस से उस की कीमत बहुत ज्यादा होगी । आज हमारी यह हालत है कि जो पेपर मिल हम कनज्यूमिंग सेन्टर के करीब भी बना रहे हैं, उस कागज की कीमत भी काफ़ी है । इसको देख कर हमें सोचना पड़ेगा कि वहां पर कितनी जल्दी पेपर मिल को लगाया जा सकता है ।

श्री महाराज सिंह भारती : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट

हो गई है और उस पर गौर किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने टाइम से केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वह पेपर मिल बहुत दूर होगी और उस का कागज महंगा पड़ेगा। क्या यह सच है कि यही बात केन्द्रीय सरकार को नागालैण्ड के विकास के काम को करने से लगातार रोक रही है ?

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : जो कोई इकनोमिक प्रोजेक्ट हमारे सामने आती है, उस को देखना पड़ता है, उस के बारे में सोचना पड़ता है।

श्री महाराज सिंह भारती : मंत्री महोदय को यह नहीं भूलना चाहिये कि नागालैण्ड की स्पेशल पोज़ीशन है और इस लिए उस के विकास कार्यक्रमों के बारे में शीघ्रता करने की आवश्यकता है।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : नागालैण्ड को और तरह से सबसिडीज़ बगैरह दी जा सकती हैं, लेकिन जब तक तमाम बातों पर गौर न किया जाये, वहां पर कोई इकानोमिक यूनिट किस तरह से लगाया जा सकता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : नागालैण्ड गवर्नमेंट के अलावा दूसरी कई सूबाई सरकारों ने भी केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह उन के क्षेत्र में कागज के कारखाने लगाने की इजाजत दे और उन को इस बारे में सहायता दे। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सिफ़ारिश की है कि गोंडा, बहराइच आदि पूर्वी ज़िलों में कागज का कारखाना लगाने की इजाजत दीजाये, जहां पर उस का सारा मैटीरियल काफी मिलता है। चूंकि हमारे देश में न्यूज़प्रिंट की कमी है और हम उस को बाहर से मंगाते हैं, इस लिए क्या सरकार इन तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखेगी और जिन राज्य सरकारों ने इस बारे में सिफ़ारिश की है, उस पर गौर कर के उन इलाकों में भी कागज के कारखाने लगाने पर विचार करेगी ?

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : पेपर मिल बगैराह तो हमने 1966 से डी-लइसेंस कर दी हैं। सवाल यह है कि पब्लिक सेक्टर में, या जो कार्पोरेशन हमने बनाया है, उसके मातहत कुछ ऐसे कारखाने लगाये जायें, जहां पेपर और न्यूज़प्रिंट बन सके। हमारा जो प्लान बन रहा है, उसके बनने के बाद यह सोचा जायेगा कि प्लान में और कार्पोरेशन के मातहत हम कितने कारखाने लगा सकते हैं और कहां कहां लगा सकते हैं सब सूबों की तरफ़ से यह मांग है। इन तमाम बातों पर गौर किया जायेगा।

श्री गुमानन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति ऐसी रही है कि जहां पर कागज उद्योग के लिये सारे साधन मौजूद हैं, सब कुछ मिलता है, वहां भी सरकार कागज उद्योग खोलने में असमर्थता प्रकट करती है। जब हम सरकार से पूछते है तो उत्तर मिलता है कि राज्य सरकार से प्रपोज़ल आये तो हम विचार कर सकते हैं। राज्य सरकारें लिखती हैं और उद्योग खड़ा हो जाता है, उनमें अधिक पूंजी लग जाती है तब फिर राज्य सरकार उनको संरक्षण देने के लिये उन उद्योगों को अपने हाथ में लेने के लिये अनुरोध करती हैं, तो यह सरकार मुकर जाती है। मैं आपको एक मिसाल दूं—बिहार में एक भी कागज का कारखाना नहीं है, विशेष रूप से उत्तर बिहार में जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर बिहार के दरभंगा जिले में जो अशोक पेपर मिल है, क्या सरकार उसको अपने हाथ में लेने जा रही हैं, क्योंकि इसके लिये बिहार की राज्य सरकार ने आपसे सिफारिश की है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि यह नागालेंड का प्रश्न है और आप बिहार के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री गुणानन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई प्रशासनिक सवाल नहीं कर रहा हूँ, यह तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि हमारे राज्य में एक भी कागज उद्योग नहीं है...

MR. SPEAKER : If I allow you now everybody will start asking about his own constituency. This question is not about Bihar. The Minister will not answer your question because I am not permitting him to answer. You put a separate question about Bihar.

श्री गुणानन्द ठाकुर : बारबार यह सवाल हम यहाँ लाते हैं, लेकिन मंत्री महोदय इसे टाल जाते हैं।

श्री ओ० प्र० त्यागी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि नागालैंड में कागज बनाने का रा-मैटीरियल बहुत बड़ी तादाद में है। नागा प्रान्त की स्थिति भारत-वर्ष में एक बड़ी विचित्र स्थिति है। उद्योगों की दृष्टि से वह सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नागालैंड और पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा नागालैंड के उद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वहां पर कागज का कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार करेगी, ताकि वह पूर्वी क्षेत्र की सप्लाई का एक केन्द्र बन सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन तमाम बातों पर गौर किया जा रहा है। इसी लिये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है, उस पर गौर करने के लिये हम ने एक कमेटी मुकर्रिर की है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर एक्शन लेंगे।

SHRI HEM BARUA : Since there is no modern industry worth the name in Nagaland, since raw materials are available in abundance for a paper factory there and since the Chief Minister of Nagaland is sore and unhappy because of the minister's refusal to set up a paper factory there in spite of all these factors in favour of a paper factory there and that unhappiness is spreading among other loyal sections of Nagas, why is it that Government is trying to bypass the just claim of Nagaland like this ?

श्री गुणानन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

MR. SPEAKER : No *vyavastha ka prasna* during Question Hour.

SHRI F. A. AHMED : The hon. member's question is based on a large number of presumptions.

SHRI HEM BARUA : Not a single presumption; they are all facts.

MR. SPEAKER : That there is no major industry in Nagaland is a fact.

SHRI HEM BARUA : The Chief Minister is sore. That also is a fact.

MR. SPEAKER : That I do not know.

SHRI F. A. AHMED : There is no question of Government of India having decided not to establish a paper mill there. The project report prepared by their advisers has been submitted to us and we are considering to what extent we can meet this demand.

SHRI HEM BARUA : It is under consideration for rejection or for acceptance ?

MR. SPEAKER : Either way it is possible.

SHRI D. C. SHARMA : We are having a plan holiday for 2 years and the fourth plan is suffering from the pangs of birth just now. May I know how much money has been spent during these plan holiday years on the economic development of Nagaland and how much money has been spent on its economic development ever since the State of Nagaland was born ?

SHRI F. A. AHMED : These figures can be supplied, They are not with me now.

श्री शिकरे : अध्यक्ष महोदय, नागालैंड की पेपर का कारखाना स्थापित करने के लिये मांग आई है । मैं मंत्री महाशय से जानना चाहता हूं कि पेपर बनाने के लिये जिस रा-मैटीरियल की जरूरत होती है, क्या वह नागालैंड में मिल सकता है ? क्या केन्द्र सरकार ने इस के लिये वहां पर कोई सर्वे किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सिर्फ रा-मैटीरियल मिलने से ही कारखाना नहीं बनता है । रा-मैटीरियल जरूर वहां पर मौजूद है ।

गोरखपुर में रेलवे संचार सेवा के लिए सूक्ष्म तरंग बुर्ज

+

*1384. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रामचरण :
श्री ब० ला० बारुपाल :
श्री मोहम्मद प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में रेलवे संचार सेवा के लिये सूक्ष्म तरंग बुर्ज बनाने के लिये किस पार्टी को ठेका दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस पार्टी ने अब तक बुर्ज बनाने का काम कभी नहीं किया है और इस मामले में वह अनुभवहीन है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस ठेके के देने में जिन अधिकारियों ने मदद की थी, उनकी पदोन्नति कर दी गई है; और

(घ) यह ठेका कितने मूल्य का है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI PARIMAL GHOSH) : (a) M/s. SAAS Engineering Company Pvt. Ltd., Calcutta.

(b) No, Sir. The firm has previous experience in this type of work, namely, fabrication, foundation, erection and testing of Microwave towers from M/s. Nippon Electric Co., Japan, for the microwave system of the P & T Department in Calcutta area.

(c) No, Sir.

(d) The value of the contract is Rs. 14,28,000.

श्री हरदयाल देवगुण : अध्यक्ष महोदय, यह रेलवे मंत्रालय का एक बहुत बड़ा घुटाला है और मैं आपकी अनुमति से रेलवे मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि यह सास इन्जीनियरिंग वर्क्स लि० और उसके साथ ही साथ टावर्स प्राइवेट लि० एक ही कम्पनियां हैं । इनके दफ्तर एक ही जगह—9, वाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता में हैं और इनके मैनेजिंग डायरैक्टर—श्री० बी० सी० गुहा—श्री परिमिल घोष के ब्रदर-इन-ला यानी इनकी पत्नी के सगे भाई हैं और इनकी अपनी कोई फैक्टरी नहीं है तथा जो टावर्स ये तैयार कर रहे हैं, वह भी एक दूसरी कम्पनी के द्वारा एक दूसरे स्थान पर मैसर्स एसोशियेटेड एस० वाई० प्राइवेट लि०, बारानगर, कलकत्ता में तैयार हो रहे हैं । इन्होंने उन को सब-कांट्रेक्ट दे रखा है तथा डी० जी० एस० डी० के लोग वहां जा कर उनके सामान का इंस्पैक्शन कर रहे हैं ? क्या इस कम्पनी को इस लिये ठेका दिया गया है कि ये उनके सम्बन्धी हैं...

MR. SPEAKER : It must be in form of a question "क्या सम्बन्धी हैं" ?

श्री हरदयाल देवगुण : ठीक है, क्या ये उनके सम्बन्धी हैं तथा इस कम्पनी का इस लाइन में कोई अनुभव नहीं हैं ?

SHRI PARIMAL GHOSH : Sir, I have no idea about the composition of the company and the names of the directors of this company. This tender was floated in the year 1966.

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह मंत्री महोदय बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER : Order, order. You have made an allegation. You must hear him. You cannot make an allegation and then not hear him. He has a right to ex-